एस.एस. राजामौली की फिल्म आर आर आर ने इतिहास रच दिया है। इस फिल्म के गाने ''नाटू नाटू'' ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में बैस्ट ओरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता है। जैसे ही इस अवॉर्ड के लिए ''नाटू नाटू'' का नाम लिया गया, पूरा हॉल इस गाने से गूंज उठा। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड समारोह में मौजूद सभी नामचीन हस्तियों ने तालियां बजाईं। राजामौली, रामचरण और जूनियर एन.टी.आर. खुशी से झूम उठे। लेकिन इस गाने की सफलता के लिए जितना क्रेडिट जूनियर एन.टी.आर., रामचरण और राजामौली को जाता है, उतना ही क्रेडिट इसके कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित को भी जाता है। प्रेम रक्षित ने ही ''नाटू नाटू'' सॉन्ग के वो शानदार डांस स्टैप्स कोरियोग्राफ किए, जिन्हें देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इसके हुक स्टैप को बहुत ज्यादा कॉपी किया जाता है। इस गीत को ऑस्कर 2023 में भी बैस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटिगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। गौरतलब है कि ''नाटू नाटू'' गाने की शूटिंग यूक्रेन में हुई थी, क्योंकि तब भारत में लॉकडाउन होने की वजह से सख्ती थी। जिस समय यह गाना शूट किया गया, उस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। ''आरआरआर'' की टीम इस गाने के साथ-साथ कुछ अहम् सीन्स की शूटिंग के लिए यूक्रेन गई थी। ''नाटू नाटू'' गाने की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ैलेन्स्की के महल में हुई। चूंकि वोलोडिमिर ज़ैलेन्स्की खुद एक एक्टर रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने ''आरआरआर'' की टीम को निराश नहीं किया और शूटिंग की इजाज़त दे दी। रामचरण और जूनियर एन.टी.आर. ने इस गाने के लिए एक महीने तक रिहर्सल किया और गाने को शूट करने में दो हफ्ते लगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आरआरआर की पूरी टीम को ट्वीट करके बधाई दी है।

राजस्थान में अब युवा कांग्रेस चुनाव के नाम पर युवा नेताओं के बीच टकराव की जमीन तैयार की जा रही है

प्रक्रिया बदली है, जिसमें नामांकन पहले होंगे और सदस्यता बाद में होगी तथा सदस्यता के साथ ही बताना होगा कि किस नेता के पक्ष में सदस्यता करवाई जा रही है

- युवा कांग्रेस की बदली हुई चुनाव प्रक्रिया में आपसी टकराव होना तय है, क्योंकि ज्यादा सदस्यता करवाने के बावजूद गारंटी नहीं है कि वह युवा नेता अध्यक्ष बनेगा ही।
- 12 से 18 जनवरी तक नामांकन होंगे, 28 जनवरी से 27 फरवरी तक होगी सदस्यता।

जयपुर, 11 जनवरी (का.प्र.)। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने में जुटे हुए हैं, वहीं राजस्थान में युवा कांग्रेस के चुनाव के नाम पर युवा नेताओं के बीच टकराव की जमीन तैयार की जा रही है। राजस्थान में बुधवार से युवक कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस बार चुनाव भी बड़ा अजीब तरह से हो रहा है कि पहले नामांकन होंगे और उसके बाद मैम्बरशिप होगी। जबकि नियम यह है कि किसी भी चुनाव में पहले मैम्बरशिप होती है। उसके बाद नामांकन होते हैं, लेकिन युवा कांग्रेस में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है।

इस बार के यूथ कांग्रेस चुनाव में नामांकन तो पहले हो ही रहे हैं, लेकिन एक नियम बहुत ही दिलचस्प है कि सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले ही तय करना पड़ेगा, कि वह किस उम्मीदवार के पक्ष में सदस्यता करवा रहा है, यानि की सदस्यता के साथ ही वोटिंग भी हो जाएगी। इस बार एक और मजेदार बात यह भी है कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से जो जितने सदस्य बनवाएगा उतना ही फायदे में रहेगा। सबसे ज्यादा सदस्य बनवाने वाले पहले तीन प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और उनमें से एक को युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में यदि ज्यादा सदस्यता के बावजूद भी पहले नंबर वाले युवा नेता को किसी कारण से अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, तो तय है कि वह इतना पैसा खर्च करने वाला वह प्रत्याशी अध्यक्ष नहीं बनने की स्थिति में शांत तो बैठेगा नहीं। पहले भी युवा कांग्रेस के जितने भी चुनाव राजस्थान में हुए हैं उनमें युवा नेताओं में ना सिर्फ संघर्ष देखने को मिला है, बल्कि कई बार सीधा टकराव भी कई बार हुआ है।

इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए वन पर्सन वन पोस्ट का फार्मूला रखा है। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में जो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी पद के लिए नामांकन भरेंगे, उन्हें पुराने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे राजस्थान में कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, ऐसे में सभी नेता निर्वतमान पदाधिकारी ही हैं।

इस बार 4 पदों के लिए ही नामांकन भरे जा सकेंगे। इनमें प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। जिला महासचिव के पद के लिए वोटिंग हटा दी गई है। नई चुनाव प्रक्रिया के जरिए यूथ कांग्रेस में गुरुवार से नामांकन का काम शुरू होगा जो 18 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 28 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस बार सदस्यता के साथ ही वोटिंग हो जाएगी। इस बार जो भी सदस्य बनेगा, उसे सेल्फी के बजाय अपना 8 सेकंड का एक वीडियो डालना पड़ेगा, जिसमें वह कहेगा कि में यूथ कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूं।

'मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश दिया जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट में वकील शैलेन्द्रनाथ मणि त्रिपाठी ने एक याचिका दायर की जिसमें मासिक धर्म के दिनों में कामकाजी महिलाओं को सवैतनिक अवकाश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान लड़कियों व महिलाओं को भारी पीड़ा होती है, वैसी ही जैसी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीज को होती है।

यह कहते हुए उन्होंने युनिवर्सिटी

- सुप्रीम कोर्ट में युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक शोध रिपोर्ट के आधार पर एक जनहित याचिका दायर की गयी है, जिसमें कहा गया है कि, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को प्रायः इतना दर्द होता है, जितना हार्ट अटैक के दौरान किसी व्यक्ति को होता है।

कॉलेज ऑफ लंदन की एक शोध रिपोर्ट का हवाला दिया। याचिका में कहा गया है कि जब कोई महिला कर्मचारी मासिक धर्म के दर्द से पीड़ित होती है तब न केवल उसकी उत्पादकता कम हो जाती है बल्कि उसके कामकाज पर भी असर पड़ता है। याचिका कर्ता ने यह भी बताया कि देश की कई कम्पनियां जोमैटो, स्विगी, बायजुस, मैगज़टर, ए.आर.सी. फ्लाय माय बिज और गोज़कूप आदि महिला कर्मियों को मासिक धर्म में सवैतनिक अवकाश देती हैं।

14 वर्षीय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लड़की ने याचिका में कहा है कि वह बच्चा पालने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से फिट नहीं है।

लड़की की मां ने वकील अमित मिश्रा की मदद से याचिका दायर की तथा मांग की है कि स्थानीय पुलिस की जानकारी में लाए बिना एम्स से गर्भपात करवाया जाए, वरना न केवल उनकी पुत्री, जो अभी अल्प वयस्क है, बल्कि सारे परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा।

हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी देना अनिवार्य है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का जिक्र किया गया है जिसमें पॉक्सो एक्ट के धारा 19 में मैडिकल पेशवरों को छूट दी गई है कि वे स्थानीय पुलिस को नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी ना दें बशर्ते, वह आपसी सहमति के यौन संबंध से गर्भवती हुई हो।

याचिका के अनुसार मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैग्नैंसी एक्ट 20 सप्ताह तक के गर्भ को गिराने की अनुमति देता है अगर रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर्स को लगता है कि इस गर्भ से महिला के जीवन को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का गंभीर खतरा है। याचिका के अनुसार मामले 6 जनवरी 2023 की अल्ट्रासाउंट रिपोर्ट के अनुसार यह गर्भ 15 सप्ताह चार दिन का है।

बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमण्डल में बड़ा बदलाव नजर आयेगा?

अपने दूसरे कार्यकाल में प्र. मंत्री मोदी ने केवल एक बार (वर्ष 2021 में) फेरबदल किया है, जबकि पिछले टर्म में उन्होंने तीन बार अपना मंत्रिमण्डल बदला था

- मंत्रियों के प्रदर्शन और सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण यह बदलाव होने की संभावना है।

नई दिल्ली, 11 जनवरी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो संसद के बजट सत्र से पहले किसी भी दिन यह बदलाव हो सकता है। जहां एक ओर आगामी चुनावों की रणनीति के मद्देनजर भाजपा जहां अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों में जुटी है। मंत्रियों के प्रदर्शन और सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण यह बदलाव होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में केवल एक बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया है, जबकि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने तीन बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया था। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह फेरबदल 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले किसी भी दिन हो सकता

बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होनी है। ऐसी राय है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार से मिले सबक का असर इस फेरबदल में दिख सकता है। साथ ही कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में राजनीतिक जरूरतों के अनुसार भी इस मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो सकता है। यह फेरबदल संभवत: आखिरी बार होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब केवल 15 महीने का समय बचा है। ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में उभरते राजनीतिक समीकरण भी फेरबदल में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

इसी तरह, ऐसी चर्चा है कि पार्टी के संगठन में भी बदलाव लाया जा सकता है। मोदी की मंत्रिपरिषद में बदलाव हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसे मंत्रियों को हटाया गया और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसके बारे में किसी ने दूर-दूर तक सोचा भी नहीं था। मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव के लिए भी मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल सुर्खियों में रहे हैं। पिछली बार प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, जबकि पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया था और उन्हें रेलवे एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए थे।

पिछले फेरबदल के बाद मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड) और शिवसेना कोटे से मंत्री रहे नेताओं के इस्तीफे से भी पद खाली हुए हैं। दोनों दल इस समय विपक्षी खेमे में हैं। फेरबदल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है, जिसे शिवसेना के अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त है। एक राय यह भी है कि भाजपा चिराग पासवान को पुरस्कृत कर सकती है, जिन्हें उनके पिता और बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने मूल पार्टी के छह सांसदों में से पांच के समर्थन से एक अलग गुट बनाया है।

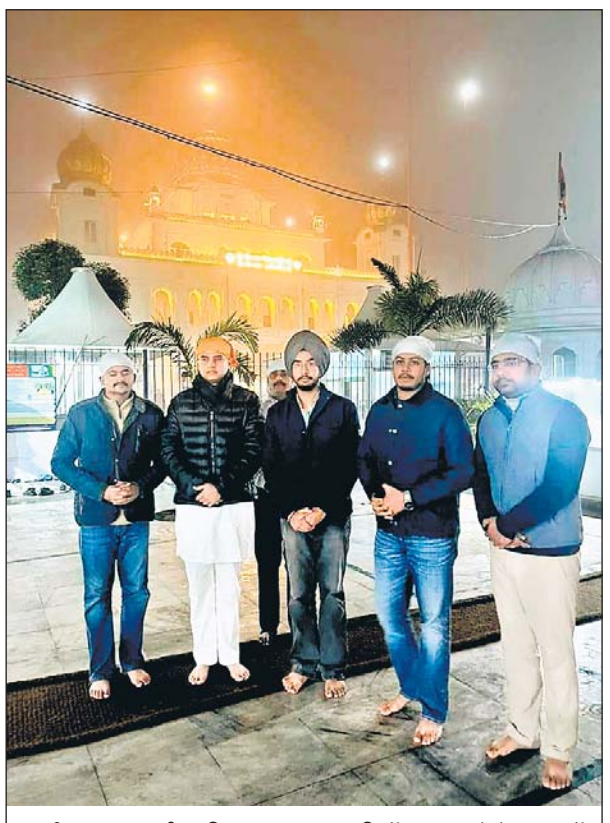

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब गये हुये हैं। मंगलवार को उन्होंने गुरूद्वारा फतेहगढ़ साहिब में ली गई एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। पायलट ने कैप्शन में लिखा, ''आज पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले हमने गुरूद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेक कर अपनी यात्रा की शुरूआत की है।''

शंघाई की 70 प्रतिशत आबादी कोविड से संक्रमित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। चीन के प्रमुख शहर शंघाई की 26 मिलियन आबादी में से 70 प्रतिशत लोग कोविड से ग्रस्त है, यह जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में दी और यकीन जताया कि कोविड संक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया है।

लेकिन चीन के इस सर्वाधिक आबादी वाले शहर में कोविड मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जाने माने फोटो जर्नलिस्ट किलाई शेन ने इस संक्रमण की

- शंघाई की आबादी 26 मिलियन है, और कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गत वर्ष कोविड में यह शहर बहुत सख्त लॉक-डाउन देख चुका है।

तस्वीरें ली है। भारी तादाद में मरीज इमरजैंसी शाखा में आ रहे है किलाई शेन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते है, ने कहा कि अस्पताल खचाखच भरे है स्टाफ के लोगों ने कहा कि उनके पास काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि उनके कई सहयोगी कोविड संक्रमित हो गए है। अस्पताल के हर कोने में मरीज है।

'रुस अगले दस वर्ष में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गंभीर चेतावनियों का समर्थन किया कि ताइवान को पुन: कब्जे में लेने के लिए चीन सैन्य आक्रमण करेगा। सत्तर प्रतिशत प्रतिभागियों ने भविष्यवाणी की कि बीजिंग ऐसा अगले 10 वर्षों में करेगा। अमेरिका के सैन्य कमाण्डरों ने वर्ष 2027 की ओर इशारा किया है, जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्थापना का 100 वां बरस है। उनके अनुसार यह आक्रमण की संभावित तिथि हो सकती है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने बीजिंग द्वारा पिछले वर्ष से पाले जा रहे इरादों को लेकर और चेतावनियां देते हुए कहा कि आक्रमण वर्ष 2024 से पूर्व संभव है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बार-बार कहा है कि वॉशिंगटन चीन के आक्रमण से ताइवान की रक्षा करेगा। लेकिन अमेरिका ने ऐतिहासिक रुप से यह बताने से परहेज किया है कि दोनों पक्षों को कार्यवाही से रोकने के लिए वह क्या करेगा। अन्य निष्कर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी पेश करते है। करीब 90 प्रतिशत प्रतिभागी मानते हैं कि वर्ष 2033 तक कम से कम एक अतिरिक्त देश परमाणु हथियार प्राप्त करेगा। उनमें से 68 प्रतिशत ने कहा कि दुनिया की छह शक्तियों के बीच परमाणु समझौते के पुनर्जीवित होने की संभावनाओं के मद्देनजर ईरान परमाणु हथियार हासिल करेगा। कुछ आशावाद का संचार करते हुए हालांकि 58 प्रतिशत विशेषज्ञों ने कहा कि उनका मानना है कि अगले दस वर्षों तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। विदेश नीति के विशेषज्ञों ने यह भी भविष्यवाणी की कि अमेरिका का भी थोड़ा पराभव होगा। जहां 71 प्रतिशत ने यह भविष्यवाणी की कि अमेरिका वर्ष 2033 तक दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बना रहेगा, वहीं 31 प्रतिशत का यह मानना है कि अमेरिका शीर्ष कूटनीतिक शक्ति बनेगा जबकि 33 प्रतिशत का यह मानना है कि वह पहले की भांति एक आर्थिक शक्ति बना रहेगा।

जात आधारित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दावा किया कि यह कदम 6 जून 2022 को बिहार के उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना की वजह से उठाया गया है। यह अधिसूचना अतार्किक और असंवैधानिक है।

उसने दावा किया कि बिहार सरकार का निर्णय, असंवैधानिक, मनमाना है और कानूनी आधार पर टिकने वाला नहीं है।

बिहार में 200 से ज्यादा जातियां हैं जो सवर्ण, ओ.बी.सी., ई.बी.सी., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में वर्गों में बांटी हुई हैं।

सभी शिकायतों बिहार की 113 जातियां ओ.बी.सी. और ई.बी.सी. में आती है और 8 सवर्ण वर्ग में आती है तथा 22 अनुसूचित जाति व 29 अनुसूचित जनजाति में आती हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी के लिये यह जरूरी है कि वे पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व, जो गुटबंदी से ग्रस्त हैं, के बारे में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दें।

पार्टी नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि पिछली गलतियों से सीखते हुये, यात्रा के माध्यम से पार्टी नेताओं को सत्तारूढ़ पार्टी आप की बखिया उधेड़नी चाहिये।

इससे पूर्व, भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब-चरण को शुरु करने से पहले, आधी बाँहों की सफेद टी-शर्ट पहने तथा पगड़ी धारण किये हुये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रात:काल गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

उस समय लोगों के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने राहुल गांधी को करीब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में, आधी बाँहों की टी-शर्ट में न केवल पैदल चलते हुये, बल्कि उस समय तो नंगे पैर चलते हुये भी देखा, जब वे सरहिन्द-बस्सी पठाना रोड पर स्थित रौज़ा शरीफ़ शेख अहमद अल-फारुक़ी अल-सरहिन्दी दरगाह गये। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग तथा अन्य पार्टी नेता भी थे। गांधी ने मंगलवार को अम्बाला जिले में यात्रा का हरियाणा-चरण पूरा करके, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की थी। वे मंगलवार की शाम को फतेहगढ़ साहिब में सरहिन्द पहुँच गये थे तथा रात को वहीं ठहरे थे। कड़ी सर्दी को चुनौती देते हुये, बहुत से पार्टी कार्यकर्ता यहाँ यात्रा के लिये इकट्ठे हो गये थे।

यात्रा के पंजाब-चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यात्रा फतेहगढ़ साहिब में सरहिन्द से शुरु होगा तथा मंडी गोविन्दगढ़, खन्ना, साहनीवाल, लुधियाना, गोराया, फगवाड़ा, जालंधर, दसीआ तथा मुकरिआन से गुजरेगी।

यात्रा का पंजाब-चरण शुरु होने से पहले, हरियाणा पी.सी.सी. अध्यक्ष ने यात्रा-ध्वज पंजाब पी.सी.सी. अध्यक्ष को सौंप दिया था।

राजा वड़िंग ने राहुल को आश्वत करते हुये कह कि पंजाब यात्रा का भव्य स्वागत करेगा तथा इससे पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा क्योंकि पंजाबी अतिथि-सत्कार के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पंजाबियों से कहा कि वे आठ दिन तक सोयें नहीं, क्योंकि यह यात्रा संविधान को बचाने के लिये आई है। उन्होंने इस यात्रा की तुलना महात्मा गांधी की डांडी यात्रा से की।

भूपिन्दर हुडा ने कहा कि चूँकि भाजपा नफरत फैलाये जा रही है, इसलिये इन्होंने (राहुल) प्रेम एवं साम्प्रदायिक फैलाने के लिये इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया है।

यात्रा के दौरान, गांधी ने विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों से भेंट की। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों से भी बातचीत की तथा उनसे उनके भविष्य के सपनों के बारे में प्रश्न किये।

कर्नाटक में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कवर कर सकें। पहले चरण में, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उत्तर कर्नाटक तथा हैदराबाद कर्नाटक में प्रचार करेंगे तथा डी.के. शिव कुमार पुराने मैसूर क्षेत्र में जायेंगे। दूसरे चरण में, सिद्धारमैया दक्षिण कर्नाटक जायेंगे तथा शिव कुमार उत्तर कर्नाटक में प्रचार करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि जनता सरकार से उकता चुकी है तथा इसे उठा फैंकने की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। नफरत तथा प्रतिशोध की राजनीति के कारण, राज्य की शांति खत्म हो गई है तथा कानून-व्यवस्था तंत्र ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जाने के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराया तथा कहा कि यह सब राज्य तथा केन्द्र सरकार की गलत नीतियों का ही नतीजा है तथा ये नीतियाँ ही किसानों के कष्ट एवं तनाव के लिये जिम्मेदार हैं। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा, ''भाजपा सरकार का फोकस 40 प्रतिशत कमीशन पर रहने के परिणामस्वरुप ही, कोविड महामारी के दौरान, 3.5 लाख से ज्यादा कर्नाटकवासियों की मृत्यु हुई थी तथा निर्दोष ठेकेदार आत्महत्या के लिये मजबूर हो गये थे।''एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एक युवा महिला और उसकी बेटी की उस समय हुई दुखद मृत्यु का जिक्र किया, जब एक दिन पूर्व बंगलोर में एक निर्माणाधीन मैट्रो पिलर उनके ऊपर गिर गया था। उन्होंने कहा कि यह घटना उस भ्रष्टाचार का स्तब्धकारी सबूत है जो आज जीवन हर क्षेत्र में व्याप्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहाँ यह याद दिलाना जरूरी है कि राज्य के ठेकेदार ने शिकायत की है कि उन्हें प्रोजैक्ट हासिल करने तथा बिल पास कराने के लिये बहुत बड़ा कमीशन देना पड़ता है।

सेना का वाहन खाई में गिरने से तीन जवानों की मौत

श्रीनगर 11 जनवरी (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) सहित तीन सैनिक शहीद हो गये। सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना कल शाम एक नियमित परिचालन कार्य के दौरान एक अग्रिम क्षेत्र में हुई। सेना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया,सेक्टर में 10 जनवरी को शाम लगभग 5:30 बजे सर्दियों के संकरे ट्रैक के साथ एक नियमित परिचालन कार्य किया गया था। आगे की पोस्ट की ओर बढ़ते समय, संकीर्ण ट्रैक के साथ लगी बर्फ टूट गई। इससे एक जेसीओ और दो जवान गहरी खाई में फिसल गए। निकटतम चौकी से सैनिकों के साथ तुरंत एक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया।

हज यात्रा के लिए वी.आई.पी. कोटा रद्द किया केन्द्र सरकार ने

हज यात्रा चाहने वाले वी.आई.पी. लोगों के लिए 5 हजार सीटें रिजर्व रखने का प्रावधान था, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे अब रद्द करने का निर्णय लिया है

- केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्र.मंत्री मोदी चाहते हैं कि, देश से वी.आई.पी. कल्चर को खत्म कर दिया जाये। उनकी इसी योजना के अनुरूप यह फैसला लिया गया है।
- यू.पी.ए. सरकार ने 2012 में हज यात्रा में वी.आई.पी. कोटा शुरु करने का फैसला लिया था।

नई दिल्ली, 11 जनवरी। केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हज के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला वी.आई.पी. कोटा अब खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने बुधवार को एक टीवी चैनल से कहा कि सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध आरक्षित हज कोटा को खत्म करने का फैसला किया है।

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वी.आई.पी. संस्कृति को खत्म करने के संकल्प का हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री इरानी ने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में आरक्षित कोटा पेश किया गया था। हज को लेकर यूपीए के शासन में वी.आई.पी. संस्कृति लागू किया गया था। जिसके तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, हज समिति और शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों के लिए एक विशेष कोटा आवंटित किया गया था। इरानी ने कहा कि हज कमेटी ने इस कोटा को समाप्त करने का आग्रह किया और विभिन्न राज्यों की सभी हज समितियों ने इसका समर्थन किया है। हज प्रक्रिया में इस वी.आई.पी. संस्कृति को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में इसे शुरू किया गया था, तब इस विशेष कोटा के तहत लगभग 5,000 सीटें थीं। इरानी ने कहा कि सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। पीएम का मानना था कि अगर हमें वी.आई.पी. संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना है तो किसी विभाग में इस तरह का कोई विशेष वर्गीकरण खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराते हुए भविष्य में गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए एक व्यापक हज नीति की घोषणा की जाएगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908